लोकसभा चुनाव 2019 -
विजय की ओर...

'नरेन्द्र मोदी फिर से'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की

जन कल्याणकारी नीतियों का संग्रह

Digital India
Power To Empower

भारतीय जनता पार्टी

मेरा बूथ
सबसे मजबूत

विषय सूची

05 जन कल्याणकारी योजनाएं

12 सशक्त युवा, स्वावलम्बी युवा

15 किसान कल्याण

20 महिला सशक्तिकरण

23 दमदार फैसले...

एक्सेलप्रिंट, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
सौभाग्य
रोशन होगा हर घर, गाँव हो या शहर
01.04.2019 तक
लगभग 4 करोड़
1912

10 करोड़ से अधिक परिवारों, 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को मिलेगा योजना का लाभ। इस स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला पहला देश बनेगा भारत।
WHO समेत विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट ने भी योजना की सराहना
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY
प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख का निःशुल्क लाभ कवर मिलेगा व योजना में परिवार के आकार और आयु किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी
SECC के जरिए लाभार्थियों को चिन्हित कर सरकार स्वयं कार्ड भेजेगी, दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं
छोटी-बड़ी कुल 473 से अधिक बीमारियों का होगा कैशलेस इलाज

जन कल्याणकारी योजनाएं

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य कवरेज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

पांच लाख रुपये तक का प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर लगभग 50 करोड़ लोगों को। देश भर में किसी भी सार्वजनिक या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा, माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगा कवरेज।

- 1084 आवश्यक दवाइयां मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाई गईं, इससे मरीजों को 15,000 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ।
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध। 4300 से अधिक स्टोर से जन सामान्य को 50%-90% से अधिक की बचत।
- AMRIT फार्मेसियों में कैंसर और हृदय संबंधित बीमारियों के लिए दवाइयां बाजार से 60% से 90% कम कीमतों पर मिलती हैं।

स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण

घुटना प्रत्यारोपण एवं कार्डिएक स्टेंट की कीमतों में भारी कमी, गरीब को हुए ये सुविधाएं सुलभ।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

इसके अंतर्गत गरीब लोगों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मिशन इंद्रधनुष

537 जिलों को कवर कर चार चरणों को पूरा किया, 86.04 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, 3.34 करोड़ बच्चों को टीके लगाए गए।

राष्ट्रीय आयुष मिशन

2400 करोड़ रुपये का लागत से चल रही राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी जैसी प्राचीन चिकित्सा विरासत को मजबूत बनाना है।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

अभी तक 400 से अधिक जन औषधि केंद्र के माध्यम से सरकार 50 से 90 प्रतिशत कम दामों पर लोगों को दवाइयां मुहैय्या करा रही है।

सौभाग्य योजना

इसके तहत अब तक कुल 2.25 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, जहां आजादी से अब तक बिजली नहीं पहुंची थी।

सोलर चरखा योजना

इसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ नौकरी पैदा कर देश के ग्रामीण इलाकों में लोगों की मदद करने की योजना है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

33.55 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

1.25 करोड़ लोगों को नए मकान मिले हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

अभी तक 15 करोड़ 19 लाख लोगों को लोन दिए जा चुके हैं

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।

5.47 करोड़ लोग लाभान्वित हुए।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

13.98 करोड़ लोग लाभान्वित हुए।

अटल पेंशन योजना

1.24 करोड़ लोग लाभान्वित हुए।

पहल योजना

डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिये 5.5 लाख करोड़ रुपये लोगों के बैंक

अकाउंट में भेजे गए हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

9.57 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण हुआ।

उजाला

31.75 करोड़ LED बल्ब गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ बांटे गए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षर बनाना है। साथ ही हर उपयुक्त परिवारों से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर कर 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को इस योजना से जोड़ना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

इस योजना के तहत 1,20,804 अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण 3,14,958 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण और 396.45 लाख बीपीएल ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 921 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 1,09,524 अविद्युतीकृत गांवों और 3,14,958 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और बीपीएल परिवारों को

218.33 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन जारी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

16,850 पिछड़े गांव में जन कल्याणकारी योजनाओं को पूर्णतया लागू किया गया।

एससी/एसटी समुदाय

कल्याण के लिए 95,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट

सुगम्य भारत, समर्थ भारत

10.5 लाख दिव्यांग जनों को सहायता तथा सहायक उपकरण वितरित करने के लिए विशेष कैंप आयोजित, सुगम्य भारत अभियान।

राइट आफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016

- डिसएबिलिटीज के प्रकारों को मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया।
- स्पीच एंड लैंग्वेज डिसएबिलिटी और विशेष लर्निंग डिसएबिलिटी को पहली बार डिसएबिलिटी माना गया।
- एसिड अटैक पीड़ितों को भी शामिल किया गया।
- डिसएबिलिटीज से पीड़ित 6-18 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 4% सीटें आरक्षित।

शादी शगुन योजना

देश में मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा के मकसद से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उन अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपये की राशि बतौर 'शादी शगुन' दे रही है जो स्नातक की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

यह देश में ऐसी पहली महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य जीवन-यापन में मदद कर रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 10.38 करोड़ है, जिसमें से 70 फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा वृद्धावस्था में होने वाली अक्षमताओं से पीड़ित है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2026 तक उम्रदराज लोगों की आबादी बढ़कर लगभग 17.3 करोड़ होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यह योजना इनके लिए अत्यधिक मददगार सिद्ध हो रही है।

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
प्रधानमंत्री
mud₹a
योजना
Udaan
खेलो इंडिया

सशक्त युवा, स्वावलम्बी युवा

स्टार्ट-अप योजना

देश भर में 2,84,549 स्टार्ट अप हब बने और 14,737 स्टार्ट अप को मान्यता दी गयी।

मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) एक गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु/लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को एक योजना शुरू की गई है। अभी तक 12 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचा है।

स्टैंडअप इंडिया

उत्तिष्ठ भारत (स्टैंड-अप इंडिया) योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना की स्थापना के लिए रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

चार साल (2016-2020) के लिए स्वीकृत 12,000 करोड़ रुपये का आवंटित बजट के साथ 10 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

खेलो इंडिया

16,15,101 लोग भारतीय खेलो इंडिया योजना के अंदर अभी तक शपथ ले चुके हैं।

नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लांच

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल देश के प्रत्येक कोने से खेल प्रतिभा खोज निकालने की सरकार की पहल है।

अटल इनोवेशन मिशन

भारत सरकार ने नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की है। स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग के साथ अटल इनोवेशन मिशन भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी हैं।

नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम

8,15,183 छात्रों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है।

उड़ान स्कीम

जम्मू एवं कश्मीर में 'उड़ान' योजना नामक यह विशेष उद्योग पहल 40,000 युवाओं को पांच साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने एवं उनमे रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) एवं निगमित क्षेत्र द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मोड में किया जा रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका
फसलों और क्षेत्रों का चयन एवं अधिसूचित करना।
फसलवार बीमा इकाई का चयन करना, बीमित राशि घोषित करना एवं फसल वार क्षतिपूर्ति स्तर का निर्धारण।
निविदा द्वारा बीमा कम्पनियों का चुनाव करना।
योजना से सम्बन्धित अधिकारियों/संस्थाओं/सरकारी विभागों/समितियों के लिए दिशा निर्देश जारी करना।
बीमा दावा गणना के लिए उपज आंकड़ा समयबद्ध उपलब्ध कराना एवं इसके लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग करना।
बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत उचित अनुमानों के आधार पर प्रत्येक मौसम के शुरू में उनको प्रीमियम सब्सिडी का 50 प्रतिशत हिस्सा निर्मुक्त करना।
स्थानीयकृत जोखिमों द्वारा प्रभावित वैयक्तिक बीमाकृत किसानों के फसल नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए बीमा कम्पनियों को सहायता देना।
अधिसूचित फसलों, क्षेत्रों एवं अन्य जानकारी को फसल बीमा पोर्टल पर डीजिटाइज़ करना।
योजनानुसार रबी 2018-19 के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 दिसम्बर है।
बीमा कराने हेतु नजदीकी बैंक/ PACS/ जनसेवा केन्द्र/ बीमा एजेंट या सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करें।

किसान कल्याण

किसानों की आय दोगुनी करने की योजना

सात सूत्रीय कार्यक्रम जिसके अंतर्गत "हर खेत को पानी", इनपुट का प्रभावी उपयोग, उपज के बाद नुकसान कम करना, गुणवत्ता में वृद्धि, विपणन (कृषि बाजार) में सुधार, जोखिम, सुरक्षा एवं सहायता, और सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए सरकार किसानों की आय दोगुनी करने पर प्रयासरत है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह किसानों की आय का सुरक्षा कवच है। इसमें खड़ी फसल के साथ-साथ बुवाई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। अब तक 14.39 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जा चुका है।

100% नीम कोटिंग और नई यूरिया नीति

अब पूरे देश में 100 फीसदी यूरिया नीम कोटेड है। इससे यूरिया की कालाबाजारी रुक गई है और किसानों को कभी इसकी किल्लत नहीं होती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गयी ताकि सिंचाई

आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधनों, नेटवर्क वितरण और फार्म लेवल अनुप्रयोगों में सर्वांगीण समाधान किया जा सके।

e-NAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट

ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना की शुरुआत की गई है जिसमें अभी तक सैकड़ों मंडियों को जोड़ा जा चुका हैं। कई मंडियों में ऑनलाइन कृषि बाज़ार ट्रेंडिग भी शुरू हो चुकी है। अब तक 1.35 करोड़ किसानों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का लाभ दिया जा चुका है।

सभी रबी फसलों की एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि

गेहूं की कीमत 1,840 रुपये प्रति क्विंटल, चना 4,620 रुपये, मसूर 4,475 रुपये तथा सरसों की 4,200 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि से किसानों को 62,635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का शुभारंभ

सरकार की इस योजना का मकसद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से डेढ़ गुना करने के एलान को मूर्तरूप देने का है। योजना के तहत किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी है। योजना में किसानों से अन्न खरीदने के लिए तीन तरह की प्रक्रिया की व्यवस्था की जा रही है। इसमें मूल्य सहायता योजना

(पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी ख़रीद और स्टॉक स्कीम की पायलट योजना शामिल है।

साइल हेल्थ कार्ड स्कीम

इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन के लिए सही मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है। सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHC) को देश में पहली बार समग्र रूप से लागू किया जा रहा है। अब तक 17.3 करोड़ किसानों को साइल हेल्थ कार्ड बांटा जा चुका है।

राट्रीय बांस मिशन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय दस्तकारों और बांस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों को हुआ अप्रत्याशित लाभ।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान - कुसुम योजना

कुसुम योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है।

गोबर धन स्कीम

मवेशियों के गोबर, कृषि से निकलने वाले कचरे, रसोई घर से निकलने वाला कचरा, इन सबको बायोगैस आधारित उर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 'गोबर

धन योजना' के तहत ग्रामीण भारत में किसानों, बहनों, भाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे गोबर और कचरे को सिर्फ कचरे के रूप में नहीं, बल्कि आय के स्रोत के रूप में देखे।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

देश में दूसरी श्वेत क्रांति लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा इन पशुओं में होने वाली बीमारियों पर लगाम लगाना भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के लैवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया जा रहा है।

उपलब्धियां

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ-104 जिलों में लिंगानुपात में सुधार, माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा

मिशन इंद्रधनुष- 86.8 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया.

प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017- सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया, दुनिया में अब तक की सबसे ज्यादा अवधि का मातृत्व अवकाश

महिला सशक्तिकरण

गर्भवती महिलाओं की देखभाल और कल्याण को बढ़ावा

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017- 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

104 चिन्हित जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार। लड़कियों की शिक्षा के लिए कई तरह की छात्रवृत्ति।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

अब तक 5.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलिंडर एवं चूल्हा दिया जा चुका है।

मुद्रा और स्टैंडअप इंडिया

मुद्रा और स्टैंडअप इंडिया से 9 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई।

ट्रिपल तलाक

ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

एकल मां के लिए पासपोर्ट

एकल मां के लिए पासपोर्ट नियम आसान बनाए गए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अभूतपूर्व वृद्धि

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिससे लगभग 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को लाभ होगा।

लाभ पैकेज के जरिए आशा वर्कर्स का सशक्तिकरण

निरीक्षण शुल्क ₹250/- से बढ़ाकर ₹300/- किया गया, ₹1000/- माह की वृद्धि की गई।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ 'एकल केंद्र' अभिसरित सहायक सेवाएं प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

देश में तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई या SSY) गर्ल चाइल्ड के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है। साल 2016-17 में SSY में 9.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है।

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

Digital India
Power To Empower

MSME

सामंजस्य एवं शान्ति के लिए योग

दमदार फैसले...

इज ऑफ डूइंग बिजनेस

भारत ने 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में पिछले चार वर्षों में 65 पायदानों की और ऊंची छलांग लगाई। विश्व बैंक द्वारा आकलन किये गये 190 देशों वाली 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में भारत वर्ष 2014 के 142वें पायदान से और ऊपर चढ़कर 2018 में अब 77वें पायदान पर पहुंच गया।

सर्जिकल स्ट्राइक

29 सितम्बर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी लांच पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचा और अनेक आतंकवादी मारे गए।

नोटबंदी

नवंबर 8, 2016 भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन देश को "काले धन की खतरनाक बीमारी" से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। नोटबंदी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील करना था और व्यवस्था में से

काले धन के प्रवाह को भी कम करना था।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

भारत ने जिस तरह से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया है, इससे न केवल हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया विस्मित है। भारतीय अंतरिक्ष क्षमताओं व इसकी तकनीकी गुणवत्ता और अपेक्षाकृत कम लागत की पूरी दुनिया में चर्चा है। अब विकसित देशों ने भी अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। फरवरी 2017 में इसरो के पीएसएलवी-सी 37 ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

योग दिवस

मौजूदा सरकार द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का पूरे उत्साह के साथ पूरी दुनिया में प्रचार व प्रसार किया जा रहा है। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि सरकार ने योग को विश्व का ब्रांड बनाने की पहल की। सरकार के प्रयासों के कारण ही योग को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया और 21 जून को विश्व योग दिवस भी घोषित किया गया। पूरे विश्व के राष्ट्रों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस दिवस को यादगार बना दिया।

डिजिटल इंडिया (गांवों तक)

डिजिटल इंडिया पर फोकस करने के साथ विकास की तमाम योजनाओं में अत्याधुनिक तकनीक के सहारे सरकार की कोशिश भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने की है, जो विश्वशक्ति के रूप में भारत की पहचान को स्थापित करने वाला साबित होगा और एक नए भारत का उदय होगा।

9.57 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने

स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 9.57 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं।

जीएसटी का सफल क्रियान्वयन

जीएसटी का सफल क्रियान्वयन हुआ। जीएसटी आज जहां तक पहुंचा है, वह स्वस्थ लोकतंत्र का परिणाम है जिसमें हर राज्य के साथ संवाद हुआ। जीएसटी पर आम सहमति होना एक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह ऐसा निर्णय है जो आम सहमति से हुआ है। सभी राज्यों ने मिलकर इसकी जिम्मेदारी ली है। दरअसल जीएसटी सहकारी संघवाद के नई ऊंचाई पर पहुंचने का सबूत है।

28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची

- जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर 2018 को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक

सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की।

- परिषद ने जीएसटी की 28 प्रतिशत की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया। इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं।

एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू कर दी, जिसकी मांग कार्यान्वयन के लिए पिछले 40 से अधिक वर्षों से लंबित थी। अब तक केंद्र सरकार ने देश के सैनिकों के लिए ओआरओपी स्कीम के तहत हजारों करोड़ रुपये दे चुकी है।

महंगाई पर नियंत्रण

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में महंगाई पर जबरदस्त नियंत्रण रखा। खुदरा महंगाई नवंबर 2018 में घटकर 2.33 फीसदी पर आ गई। यह पिछले डेढ़ साल का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले जून 2017 में खुदरा महंगाई 1.46 फीसदी रही थी।

एमएसएमई सेक्टर की चिंता

देश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर को कई सुविधाएं दी। इस क्षेत्र की इकाइयों को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने के लिये आनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। इसके साथ ही इन इकाइयों को कर्ज पर ब्याज सहायता, श्रम एवं कंपनी कानून में छूट और इनके लिये पर्यावरण नियमों के अनुपालन को आसान बनाया गया।

भ्रष्टाचार मुक्त सरकार

मोदी सरकार ने 'भ्रष्टाचार मुक्त' प्रशासन दिया है और भारत आज विदेशी निवेश पर निर्भर 'पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं' की सूची से निकलकर वैश्विक मंच पर 'आकर्षक गंतव्य' बन गया है।

कौशल विकास

- पहली बार कौशल विकास मंत्रालय बनाकर इस पर पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और इनकम टैक्स में छूट के माध्यम से स्थायी रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- इसी तरह अप्रेन्टिसशिपएक्ट में सुधार करके अप्रेन्टिसों की संख्या बढ़ाई गई है और अप्रेन्टिस के दौरान मिलने वाले स्टाईपेंड में भी बढोतरी की गई है।

सबसे लम्बा रेल-रोड पुल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा रेल-रोड पुल देश को समर्पित किया। असम में बने बोगीबील ब्रिज की कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर

है, जिस पर नीचे रेलगाड़ियां और ऊपर बसें एक साथ दौड़ सकेंगी। यह पुल सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है।

सबसे लंबी सुरंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक और देश की सबसे लंबी चेनानी-नाशरी सुरंग का उद्घाटन किया। यह एक ऐसा टनल है, जिसके भीतर और बाहर लगे हैं 124 सीसीटीवी कैमरे। इस टनल की लबाई 9.2 किलोमीटर है ।

आतंकवाद, अलगाववाद पर नियंत्रण

- जम्मू एवं कश्मीर में ठोस आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया हुआ और स्थानीय निकाय चुनावों का निर्विघ्न संचालन हुआ। बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति में काफी सुधार हुआ। पश्चिमी सीमाओं पर हमारे सुरक्षा बलों ने युद्धविराम उल्लंघनों का उतने ही कड़े तौर पर जवाब दिया और घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया।
- पूर्वोत्तर में सुरक्षा परिदृश्य लगातार सुधर रहा है। वर्ष 1997 के बाद से पिछले दो दशकों में पहली बार पिछले साल विद्रोह की घटनाएं और सुरक्षा बलों व नागरिकों के बीच हताहतों की संख्या सबसे कम दर्ज की गईं। जहां त्रिपुरा और मिजोरम में अब करीब करीब कोई विद्रोह नहीं बचा है, वहीं अन्य राज्यों और इस क्षेत्र

में सुरक्षा स्थिति में सुधार देखा गया है।

सशक्त अर्थव्यवस्था

इस समय भारत की विकास दर चीन को पछाड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक है। विश्व बैंक जैसे जाने-माने कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का आकलन है कि आने वाले वर्षों में भारत की विकास दर 8 फीसदी से भी अधिक हो सकती है।

सागरमाला

8 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा निवेश से 500 से अधिक बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, सड़कों व नए बंदरगाहों का विकास हो रहा है।

अनारक्षित वर्ग 10% आरक्षण

मोदी सरकार के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाया गया संविधान (124वां संशोधन) विधेयक संसद में पारित हो गया। यह निर्णय मोदी सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा की पुष्टि करता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में ऐतिहासिक फैसला

उन्हें मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ, जिनके

- परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है
- जिनके परिवार के पास :
  - 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है
  - 1000 वर्ग फुट से कम आवासीय भवन है
  - नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम आवासीय भूमि है
  - नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में 200 गज से कम आवासीय भूमि है

स्रोत - भारत सरकार

बूथ जीता

चुनाव जीता

लोकसभा चुनाव 2019 - विजय की ओर...

‘फिर एक बार, मोदी सरकार’

भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई और विकास का सुकार्य कर डाला, दिशा बदली और देश के करोड़ों लोगों तक सीधे-सटीक विकास पहुंचाने की योजनाएं बनाईं। 126 से ज्यादा योजनाएं लेकर गरीब के जीवन स्तर को उठाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया है।

– अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

भारतीय जनता पार्टी

6–A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली –110002